

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या- 161/2020-21(PH)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
03.9.20	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कारवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ड्रापाक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अगुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खारा भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि मौजा- <u>गौड़तोपा</u> थाना न०- <u>184</u>, खाता संख्या- <u>78</u> प्लॉट संख्या- <u>2357</u>, रकबा- <u>50 गीठ</u> एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- <u>2</u> के पृष्ठ संख्या- <u>556</u> पर जमाबंदी रैयत <u>बुधनी मैसाइन पति मौडा मांकी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उद्देश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>19/9/2020</u> को उपस्थापित करें।</p>	<p><u>03/9/20</u></p> <p>अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

नाद अभिलेख संख्या- 161/20-2(VIII) / 2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act,1950)

सूचना

नाम बुधनी मेझाइन  
पति - मौडा मांझी  
साठ - गौड़तीपा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मौजा- गौड़तीपा थाना नं०-  
184 खाता नं०- 98 खेसरा नं०- 2357  
रकबा- 50 बीघा, से संबंधित आपके नाम से ह० नं०- VIII के पंजी II भाग 2  
के पृष्ठ 556 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम  
से जांचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 19/9/2020 को समय-11.00 बजे पूर्वाह्न  
में उक्त भूमि का रिटर्न-I भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत  
जमींदार रसीदों फार्म ड एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि  
पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना  
पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ  
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज  
जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

03/9/20

अंचल अधिकारी  
2119-455

तिथि :-

स्थान :-

अतिरिक्त उपस्थिति: कौटुंबिक सम्बन्ध: निम्नलिखित विधि को उपस्थिति  
देना/उपस्थिति देना के अभाव में इस कानून के अन्तर्गत किसी प्रकार का प्रशासनिक  
कार्यवाही नहीं किया जाये और न ही अन्वय का ही क्या करे।

इस कानून के अन्तर्गत जो अन्वय कानून द्वारा दिये गये विधान (अनुच्छेद) के अन्तर्गत  
1960 की धारा 2(1) के अन्तर्गत उपस्थिति को एक कानून के अन्तर्गत ही जानी है। अन्वय  
कार्यवाही के अन्तर्गत कानून के अन्तर्गत उपस्थिति को कानून।

अन्वय अधिकारी  
गोविन्दपुर

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

19/11/20

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर